

SUPREME COURT OF INDIA | 2026

15 IMPORTANT JUDGMENTS

मामले के तथ्य · विवादित विधिक प्रश्न
न्यायालय का निर्णय · विधिक सिद्धांत

Criminal Law · Constitutional Law · Civil Law · Labour Law

TARGET **FOR IQ**

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की आवश्यक शर्तें

Chittibarika Chandra Shekar v. State of Telangana

CRIMINAL LAW | IPC 306 • BNS 108

मामले की पृष्ठभूमि

- एक महिला और प्रथम अभियुक्त में सहमति से संबंध था; कुछ समय वे साथ भी रहे।
- रिश्ते में विवाद और शादी से इनकार के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली।
- अभियुक्त और उसके परिजनों पर IPC 306/34 के अंतर्गत मुकदमा चला।

विवादित प्रश्न

क्या शादी से इनकार और उसके बाद आत्महत्या अपने-आप Suicide के लिए उकसावा सिद्ध करता है?

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की आवश्यक शर्तें

Chittibarika Chandra Shekar v. State of Telangana

CRIMINAL LAW | IPC 306 • BNS 108

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- नहीं। केवल संबंध टूटना या शादी से इनकार अपने-आप अपराध नहीं है।
- आत्महत्या के लिए उकसावा, आवश्यक आपराधिक मंशा तथा आरोपों में ठोस आधार देखना होगा।
- इन तथ्यों में Supreme Court ने छह अभियुक्तों की कार्यवाही रद्द की।

विधिक सिद्धांत

IPC 306 के लिए दुष्प्रेरण के विधिक तत्व व आपराधिक मंशा का आधार आवश्यक है।

निर्णय का दायरा: परिस्थिति में निरंतर प्रताड़ना या सक्रिय उकसावा हो तो मामला अलग हो सकता है।

पीड़ित का शीघ्र आपराधिक सुनवाई का अधिकार

Renuka Jain v. State (NCT of Delhi)

ARTICLE 21 | SPEEDY TRIAL | BNSS 528

मामले की पृष्ठभूमि

- धोखाधड़ी संबंधी मामला कई वर्षों से Trial Court में लंबित था।
- पीड़िता ने शीघ्र सुनवाई की मांग की; Delhi High Court ने आवेदन को तुच्छ बताकर ₹10,000 लागत लगाई।
- उस आदेश को Supreme Court में चुनौती दी गई।

विवादित प्रश्न

क्या शीघ्र सुनवाई की मांग केवल अभियुक्त का अधिकार है, या पीड़ित का भी?

पीड़ित का शीघ्र आपराधिक सुनवाई का अधिकार

Renuka Jain v. State (NCT of Delhi)

ARTICLE 21 | SPEEDY TRIAL | BNSS 528

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- पीड़ित आपराधिक कार्यवाही में केवल एक Witness नहीं है; उसे न्याय में वास्तविक हित है।
- Speedy Trial की मांग अभियुक्त के साथ-साथ पीड़ित भी कर सकता है।
- High Court का लागत वाला आदेश हटाया; Trial Court को एक वर्ष में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश।

विधिक सिद्धांत

BNSS 528 के तहत पीड़ित भी आपराधिक मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के निर्देश मांग सकता है।

निर्णय का दायरा: शीघ्र सुनवाई, अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को समाप्त नहीं करती।

Civil Judge भर्ती में अधिवक्ता प्रैक्टिस की पात्रता

Bhumika Trust v. Union of India

JUDICIAL SERVICE | CIVIL JUDGE ELIGIBILITY

मामले की पृष्ठभूमि

- 20 मई 2025 के निर्देश में Civil Judge (Junior Division) के लिए 3 वर्ष की Bar Practice तय हुई थी।
- नए उम्मीदवारों और दिव्यांग अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को लेकर पुनर्विचार हुआ।
- तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 बहुमत से संक्रमणकालीन व्यवस्था दी।

विवादित प्रश्न

Practice requirement बदलते समय नए एवं पुराने Recruitment Notifications पर कौन-से नियम लागू होंगे?

Civil Judge भर्ती में अधिवक्ता प्रैक्टिस की पात्रता

Bhumika Trust v. Union of India

JUDICIAL SERVICE | CIVIL JUDGE ELIGIBILITY

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- 31.03.2027 तक संक्रमणकालीन भर्ती विज्ञापनों के लिए Law Graduates तीन वर्ष की Bar Practice के बिना आवेदन कर सकते हैं।
- चयनित उम्मीदवार: 1 वर्ष State Judicial Academy Training और 1 वर्ष Law Clerkship (6 महीने District Court, 6 महीने High Court)।
- 01.04.2027 या बाद के विज्ञापनों में 1 वर्ष वास्तविक District Court Practice और सत्यापित Certificate आवश्यक।

विधिक सिद्धांत

2027 में भर्ती विज्ञापन जारी होने की तारीख से प्रैक्टिस की शर्त बदलती है।

निर्णय का दायरा: 1 अप्रैल 2027 से एक वर्ष की वास्तविक District Court Practice और प्रमाण-पत्र जरूरी।

उत्तर प्रदेश Gangsters Act और अपराध का वैधानिक आधार

Shiv Pratap Singh @ Chinu v. State of U.P.

UP GANGSTERS ACT | ARTICLE 20(1)

मामले की पृष्ठभूमि

- दो मामलों में UP Gangsters Act, 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों को चुनौती दी गई।
- अभियुक्त को Gangster मानने में Gang Chart और नियमों की भूमिका मुख्य थी।
- सवाल था: परिभाषा, नियम और दंड के बीच वास्तविक अपराध की वैधानिक नींव क्या है?

विवादित प्रश्न

क्या अधिनियम में स्वतंत्र अपराध बनाए बिना केवल दर्जे या Gang Chart के आधार पर दंड हो सकता है?

उत्तर प्रदेश Gangsters Act और अपराध का वैधानिक आधार

Shiv Pratap Singh @ Chinu v. State of U.P.

UP GANGSTERS ACT | ARTICLE 20(1)

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Court ने कहा कि Act की परिभाषा और नियम अपने-आप नया दंडनीय अपराध नहीं बना सकते।
- केवल प्रशासनिक Gang Chart के जरिए अपराध बनाना विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है।
- संबंधित दोनों मुकदमों की Gangsters Act कार्यवाही रद्द की गई।

विधिक सिद्धांत

किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए विधि में अपराध के आवश्यक तत्व निर्धारित होने चाहिए।

निर्णय का दायरा: सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अभियोजन रद्द किए; इसे पूरे अधिनियम का निरसन नहीं माना गया।

विवाह-सदृश संबंध और IPC धारा 498A

Dr. Lokesh B.H. v. State of Karnataka

IPC 498A | LIVE-IN RELATIONSHIP

मामले की पृष्ठभूमि

- प्रश्न था कि विवाह-जैसे संबंध में महिला के साथ क्रूरता पर IPC 498A लागू किया जा सकता है या नहीं।
- शिकायत में पूर्व विवाह छिपाने, दहेज उत्पीड़न और शारीरिक चोट के आरोप थे।
- Court ने Penal Statute की व्याख्या और महिलाओं की सुरक्षा दोनों पर विचार किया।

विवादित प्रश्न

क्या Marriage-like Live-in में पुरुष को Section 498A के लिए "Husband" माना जा सकता है?

विवाह-सदृश संबंध और IPC धारा 498A

Dr. Lokesh B.H. v. State of Karnataka

IPC 498A | LIVE-IN RELATIONSHIP

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- IPC 498A के प्रयोजन के लिए वास्तविक विवाह-सदृश संबंध के स्वरूप और विवाह करने के आशय पर विचार किया जा सकता है।
- केवल Live-in Relationship पर्याप्त नहीं; शिकायतकर्ता को आवश्यक प्रारंभिक तथ्यों का आधार देना होगा।
- Arnesh Kumar में निर्धारित Arrest Safeguards प्रासंगिक हैं; कोर्ट ने वर्तमान कार्यवाही निरस्त नहीं की।

विधिक सिद्धांत

IPC 498A के लिए सभी Live-in संबंध पर्याप्त नहीं; विवाह-सदृश प्रकृति का परीक्षण जरूरी है।

निर्णय का दायरा: निर्णय ने Section 498A IPC के संदर्भ में निष्कर्ष दिया; हर Live-in पर स्वतः लागू नहीं।

न्यायिक निर्णयों में AI से निर्मित फर्जी मिसालें

Pooja Ramesh Singh v. J&K Bank Ltd.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE | JUDICIAL ETHICS

मामले की पृष्ठभूमि

- एक Insolvency विवाद में NCLT और NCLAT के निर्णय विवादित बने।
- न्यायिक निर्णय में ऐसे कथित precedents का सहारा लिया गया जो वास्तविक नहीं थे।
- Supreme Court ने AI से तैयार Hallucinated Citations की गंभीरता पर चर्चा की।

विवादित प्रश्न

क्या AI-generated गलत या काल्पनिक मामलों पर आधारित फैसला कायम रह सकता है?

न्यायिक निर्णयों में AI से निर्मित फर्जी मिसालें

Pooja Ramesh Singh v. J&K Bank Ltd.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE | JUDICIAL ETHICS

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Court ने संबंधित NCLT और NCLAT आदेश हटाए।
- AI शोध में मदद कर सकती है; पर अंतिम Judicial Decision मानव न्यायाधीश के नियंत्रण में रहना चाहिए।
- किसी भी केस का नाम, Citation और Ratio मूल निर्णय से मिलाना आवश्यक।

विधिक सिद्धांत

Judicial Precedent की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी न्यायिक निर्णयकर्ता की रहती है।

निर्णय का दायरा: NCLT तथा NCLAT के विवादित आदेश निरस्त कर दिए गए।

यौन अपराधों में Preparation और Attempt का अंतर

In Re: Allahabad HC Order dated 17.03.2025

ATTEMPT VS PREPARATION | SEXUAL OFFENCES

मामले की पृष्ठभूमि

- Allahabad High Court ने एक नाबालिग के साथ यौन अपराध संबंधी मामले में Attempt की जगह Preparation माना था।
- उस आदेश से संबंधित कानूनी प्रश्न Supreme Court की स्वतः संज्ञान वाली कार्यवाही में उठा।
- मामला Sexual Offences में Judicial Sensitivity से भी जुड़ा था।

विवादित प्रश्न

आरोपी के कार्य किस चरण पर केवल तैयारी से आगे बढ़कर दंडनीय Attempt बनते हैं?

यौन अपराधों में Preparation और Attempt का अंतर

In Re: Allahabad HC Order dated 17.03.2025

ATTEMPT VS PREPARATION | SEXUAL OFFENCES

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- कृत्यों की निरंतरता, आपराधिक उद्देश्य और अपराध के करीब पहुँचे कदम महत्वपूर्ण हैं।
- Court ने High Court का संबंधित आदेश पलटते हुए Attempt का प्रथमदृष्टया आधार स्वीकार किया।
- यौन अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशील न्यायिक व्यवहार पर भी बल दिया।

विधिक सिद्धांत

अपराध की दिशा में प्रत्यक्ष कार्यवाही, केवल तैयारी से आगे जाकर Attempt बन सकती है।

निर्णय का दायरा: कोर्ट ने मामले में Attempt का प्रथमदृष्टया आधार माना।

जीवन-रक्षक उपचार की वापसी और गरिमा का अधिकार

Harish Rana v. Union of India

ARTICLE 21 | PASSIVE EUTHANASIA

मामले की पृष्ठभूमि

- दुर्घटना के बाद मरीज वर्षों से Permanent Vegetative State में था।
- मरीज की अवस्था और उपचार के लाभ का चिकित्सकीय आकलन किया गया।
- प्रश्न था कि Clinically Assisted Nutrition & Hydration हटाना कानूनी रूप से संभव है या नहीं।

विवादित प्रश्न

क्या रोगी के Best Interests में जीवन-रक्षक उपचार वापस लेना Article 21 के अनुकूल है?

जीवन-रक्षक उपचार की वापसी और गरिमा का अधिकार

Harish Rana v. Union of India

ARTICLE 21 | PASSIVE EUTHANASIA

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Court ने निर्धारित मेडिकल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा के साथ उपचार वापस लेने की अनुमति दी।
- Right to Die with Dignity और Best Interests of Patient के सिद्धांतों पर जोर दिया।
- Common Cause (2018) के Passive Euthanasia Framework को संदर्भ बनाया।

विधिक सिद्धांत

CANH जैसे उपचार को वापस लेने में मरीज के हित और निर्धारित चिकित्सा प्रक्रिया निर्णायक हैं।

निर्णय का दायरा: यह Active Euthanasia को सामान्य वैधानिक अनुमति देने वाला निर्णय नहीं है।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ADR v. Election Commission of India

ELECTION LAW | ARTICLE 324 | SIR

मामले की पृष्ठभूमि

- बिहार की मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को चुनौती दी गई।
- याचिकाओं में प्रक्रिया, नागरिकता की जाँच और मताधिकार से जुड़ी आशंकाएँ उठीं।
- Court ने Article 324, RP Act 1950 और Electoral Rules पर विचार किया।

विवादित प्रश्न

क्या Election Commission सूची का गहन पुनरीक्षण और पात्रता-संबंधी जाँच कर सकता है?

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ADR v. Election Commission of India

ELECTION LAW | ARTICLE 324 | SIR

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Court ने Bihar SIR के लिए ECI की शक्ति और प्रक्रिया को कानूनी माना।
- मतदाता सूची की पात्रता देखना और किसी की नागरिकता का अंतिम निर्धारण अलग बातें हैं।
- Electoral Rolls में बदलाव वैधानिक प्रक्रिया, उचित अवसर एवं सुरक्षा के अधीन होगा।

विधिक सिद्धांत

मतदाता सूची की पात्रता और नागरिकता के अंतिम विधिक निर्धारण में अंतर है।

निर्णय का दायरा: Electoral Roll में संशोधन वैधानिक प्रक्रिया और अवसर दिए जाने के अधीन है।

विधवा की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार

Sultan Singh v. Financial Commissioner, NCT Delhi

HINDU SUCCESSION | DELHI LAND REFORMS

मामले की पृष्ठभूमि

- दिल्ली की कृषि भूमि में विधवा के Bhumidhari अधिकार और बाद के उत्तराधिकार पर विवाद था।
- मुख्य प्रश्न Delhi Land Reforms Act, 1954 की Section 51(2) से जुड़ा था।
- Hindu Succession Act, 1956 की Section 14(1) का प्रभाव भी जांचा गया।

विवादित प्रश्न

1956 कानून के बाद विधवा का पहले से प्राप्त सीमित भूमि-अधिकार पूर्ण स्वामित्व बनता है या नहीं?

विधवा की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार

Sultan Singh v. Financial Commissioner, NCT Delhi

HINDU SUCCESSION | DELHI LAND REFORMS

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Section 14(1) पूर्व से विद्यमान वैध सीमित अधिकार को पूर्ण स्वामित्व में बदल सकती है।
- विधवा के पास पहले कोई कानूनी हित होना आवश्यक; धारा शून्य से नया अधिकार नहीं बनाती।
- इन तथ्यों में Supreme Court ने अपील खारिज की और Delhi HC का निष्कर्ष कायम रखा।

विधिक सिद्धांत

HSA धारा 14(1) पहले से प्राप्त सीमित स्वामित्व को वैधानिक शर्तों पर पूर्ण बनाती है।

निर्णय का दायरा: निर्णय Delhi Land Reforms Act की धारा 51(2) और 53 से भी संबंधित है।

अस्थायी निषेधाज्ञा और अपीलीय हस्तक्षेप

Shruti Manav Sharma v. Sunanina Singh

CPC ORDER 39 | TEMPORARY INJUNCTION

मामले की पृष्ठभूमि

- पारिवारिक कंपनियों, संपत्ति और हस्तांतरण से जुड़े विवाद में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई।
- एकल न्यायाधीश के विवेकाधीन आदेश में Division Bench ने हस्तक्षेप किया।
- Supreme Court ने अंतरिम न्यायिक विवेक और Appellate Review की सीमा तय की।

विवादित प्रश्न

क्या Appeal Court केवल अलग राय होने पर Injunction वाले आदेश को पलट सकता है?

अस्थायी निषेधाज्ञा और अपीलीय हस्तक्षेप

Shruti Manav Sharma v. Sunanina Singh

CPC ORDER 39 | TEMPORARY INJUNCTION

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Temporary Injunction के तीन तत्व: Prima Facie Case, Balance of Convenience, Irreparable Injury।
- Appeal Court मनमाने, विकृत या गलत सिद्धांत वाले आदेश में ही हस्तक्षेप करे।
- Interim Stage पर पूरे मुकदमे का Mini-Trial अनुचित; Single Judge का आदेश बहाल हुआ।

विधिक सिद्धांत

Order 39 CPC: Prima Facie Case, Balance of Convenience, Irreparable Injury।

निर्णय का दायरा: अंतरिम आदेश अंतिम स्वामित्व या मुकदमे के गुण-दोष का निर्णय नहीं होता।

अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक धोखाधड़ी का अंतर

Parag Kishore Satoskar v. State of Jharkhand

BNS 316, 318 | CONTRACT VS CHEATING

मामले की पृष्ठभूमि

- कपूर (Camphor) व्यापार की Distributorship और Advance Payment पर विवाद था।
- व्यावसायिक लेन-देन के बाद पक्षों में देयता व माल की आपूर्ति को लेकर मतभेद हुआ।
- BNS 316(2), 318(4) व 3(5) के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी गई।

विवादित प्रश्न

क्या हर Contract Breach को Cheating या Criminal Breach of Trust माना जा सकता है?

अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक धोखाधड़ी का अंतर

Parag Kishore Satoskar v. State of Jharkhand

BNS 316, 318 | CONTRACT VS CHEATING

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- मात्र भुगतान/सप्लाई विवाद अपने-आप अपराध नहीं बनता।
- Cheating में शुरुआत से छलपूर्ण या बेईमान इरादा, तथा अन्य अपराधों के अलग तत्व जरूरी।
- इन तथ्यों में Supreme Court ने FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द की।

विधिक सिद्धांत

Cheating के लिए शुरुआत में कपटपूर्ण या बेईमान आशय का आधार आवश्यक है।

निर्णय का दायरा: समझौता उल्लंघन अपने-आप Criminal Breach of Trust अथवा Cheating नहीं है।

आपराधिक अपील में देरी और दोषमुक्ति

Arjun Jani @ Tuntun v. State of Orissa

CRIMINAL APPEAL | EVIDENCE | ARTICLE 21

मामले की पृष्ठभूमि

- हत्या के मामले में दोषसिद्ध व्यक्ति की जेल से की गई Appeal देरी के कारण आगे नहीं बढ़ी।
- Appeal दायर करने में 3157 दिनों की देरी थी; व्यक्ति लगभग 22 वर्ष जेल में रहा।
- Supreme Court ने साक्ष्य की विश्वसनीयता और न्याय तक पहुँच पर विचार किया।

विवादित प्रश्न

कैदियों की Appeal में विलंब और असंगत Eyewitness Evidence का क्या प्रभाव होगा?

आपराधिक अपील में देरी और दोषमुक्ति

Arjun Jani @ Tuntun v. State of Orissa

CRIMINAL APPEAL | EVIDENCE | ARTICLE 21

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- जेल से की गई Appeal में देरी माफ करने हेतु व्यावहारिक, उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- एकमात्र Eyewitness की कहानी में गंभीर संदेह और विरोधाभास पाए गए।
- दोषसिद्धि रद्द करके अभियुक्त बरी; उसके पुनर्वास में मदद का निर्देश।

विधिक सिद्धांत

जेल से अपील करने वालों की देरी का आकलन न्याय तक वास्तविक पहुँच के साथ किया जाए।

निर्णय का दायरा: गवाह की विश्वसनीयता में गंभीर संदेह पर दोषसिद्धि रद्द हुई।

मृत्युदंड में फाँसी की संवैधानिक स्थिति

Rishi Malhotra v. Union of India

DEATH PENALTY | ARTICLE 21 | BNSS 393(5)

मामले की पृष्ठभूमि

- याचिका में CrPC 354(5) / BNSS 393(5) के तहत फाँसी की विधि को चुनौती दी गई।
- कहा गया कि कम पीड़ादायक वैज्ञानिक विकल्पों पर विचार होना चाहिए।
- पूर्व निर्णय Deena v. Union of India की वैधता भी प्रश्न में थी।

विवादित प्रश्न

क्या उपलब्ध नए प्रमाण पुराने निर्णय को बदलने या बड़ी पीठ भेजने के लिए पर्याप्त थे?

मृत्युदंड में फाँसी की संवैधानिक स्थिति

Rishi Malhotra v. Union of India

DEATH PENALTY | ARTICLE 21 | BNSS 393(5)

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- Court ने उपलब्ध सामग्री पर पुराने Deena निर्णय पर पुनर्विचार जरूरी नहीं माना।
- Hanging के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई।
- भविष्य में ठोस वैज्ञानिक या मेडिकल प्रमाण सामने आएँ तो संवैधानिक पुनः परीक्षण संभव।

विधिक सिद्धांत

उपलब्ध साक्ष्य पर फाँसी से Execution को चुनौती देने वाली याचिका अस्वीकार हुई।

निर्णय का दायरा: नई वैज्ञानिक सामग्री सामने आने पर पुनर्विचार की संभावना को नकारा नहीं गया।

Labour Law में Industry की परिभाषा और Triple Test

State of U.P. v. Jai Bir Singh

NINE-JUDGE BENCH | LABOUR LAW | INDUSTRY

मामले की पृष्ठभूमि

- Social Forestry Department “Industry” है या नहीं, इस विवाद से बड़ी संवैधानिक चर्चा शुरू हुई।
- 1978 के Bangalore Water Supply निर्णय के Triple Test की समीक्षा का प्रश्न था।
- नौ न्यायाधीशों ने कई अलग-अलग Opinions दिए; नए Test पर स्पष्ट बहुमत नहीं उभरा।

विवादित प्रश्न

क्या पुराने Industrial Disputes Act की Section 2(j) की व्याख्या बदलनी चाहिए?

Labour Law में Industry की परिभाषा और Triple Test

State of U.P. v. Jai Bir Singh

NINE-JUDGE BENCH | LABOUR LAW | INDUSTRY

न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष

- नौ न्यायाधीशों के बीच Bangalore Water Supply के Triple Test पर विभिन्न मत व्यक्त हुए।
- पुराने Industrial Disputes Act के लंबित विवादों में प्रचलित Triple Test का प्रभाव बना रहा।
- Industrial Relations Code, 2020 की अलग परिभाषा को उसके वैधानिक पाठ से लागू किया जाएगा।

विधिक सिद्धांत

पुराने ID Act विवादों में Bangalore Water Supply का Triple Test प्रासंगिक बना रहा।

निर्णय का दायरा: Industrial Relations Code, 2020 की वैधानिक परिभाषा अलग से लागू होती है।